

वैश्विक समस्या बनने की ओर बढ़ रहा वेनेजुएला का संकट

संदर्भ

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला इस समय अभूतपूर्व राजनीतिक संकट के दौर से गुज़र रहा है और यह वहाँ लंबे समय से जारी आर्थिक संकट की देन है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे वरिध प्रदर्शन हसिक हो गए हैं। प्रमुख वपिक्षी नेता जुआन गाइदो ने स्वयं को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। वेनेजुएला के इस संकट ने विश्व को भी दो हसिसों में बाँट दिया है और धीरे-धीरे यह संकट वैश्विक रूप लेने की ओर अग्रसर है। अमेरिका और यूरोपीय देश वेनेजुएला के वपिक्षी नेता के समर्थन में हैं तो रूस और चीन जैसे देश खुलकर मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पक्ष में हैं।

वेनेजुएला का वर्तमान संकट और दो खेमों में बंटा विश्व

- वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे वरिध प्रदर्शन हसिक हो गए हैं।
- प्रमुख वपिक्षी नेता गाइदो ने स्वयं को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया और उन्हें अमेरिका, कनाडा तथा ब्राज़ील, कोलंबिया एवं अर्जेंटीना जैसे ताकतवर पड़ोसी देशों का समर्थन मलि गया है।
- यूरोपीय संघ ने भी वेनेजुएला में फरि से चुनाव कराए जाने की मांग की है और गाइदो के नेतृत्व वाली नेशनल असेंबली का समर्थन कयिा है।
- रूस, चीन और कुछ अन्य देशों ने निकोलस मादुरो के समर्थन का एलान कयिा है। रूस ने चेतावनी दी है कि गाइदो की घोषणा से 'अराजकता और रक्तपात' का सीधा रास्ता खुल गया है।
- चीन भी वेनेजुएला में कसिी वदिशी मध्यस्थता का वरिधी है। चीन का कहना है कि वह वेनेजुएला की राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और स्थायित्व बचाए रखने के प्रयासों का समर्थन करता है।
- तुर्की, ईरान, मेक्सिको, क्यूबा और कुछ अन्य देशों ने भी निकोलस मादुरो को समर्थन देने का एलान कयिा है। बोलीविया, अल-सलवाडोर और निकारागुआ जैसे देशों से भी उन्हें समर्थन मलिा है।
- एक नवीनतम घटनाक्रम में रूस ने एक बार फरि संकट सुलझाने के लयि मध्यस्थता की पेशकश की है...और वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने स्वघोषित राष्ट्रपति जुआन गाइदो के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है।

भारत पर क्या असर पड़ेगा?

- वेनेजुएला में राजनीतिक और आर्थिक संकट गहरा गया है, जसिसे भारत की चिंता बढ़ गई है।
- अमेरिका के अलावा केवल भारत ही ऐसा देश है जो वेनेजुएला को नकदी देकर तेल खरीदता है।
- वेनेजुएला से तेल खरीदने के मामले में भारत शीर्ष देशों में से एक है।
- भारत जनि देशों से तेल आयात करता है वेनेजुएला उनमें चौथा बड़ा देश है।
- ईरान पर प्रतिबंधों के कारण पहले ही भारत को तेल आयात में मुश्किलों से गुज़रना पड़ रहा है।
- अमेरिका द्वारा वेनेजुएला की तेल कंपनयिों पर प्रतिबंध भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है।
- भारत ने वेनेजुएला के साथ हाइड्रोकार्बन सेक्टर में सहयोग के लयि द्वपिक्षीय समझौता भी कयिा है तथा वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में निवेश भी कयिा है।
- भारत में तेल उद्योग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेनेजुएला पर नज़र रखे हुए है, क्यौंकि देर से भुगतान होने की वज़ह से उन्हें नुकसान होने के बावजूद भारत के दवा उद्योग के लयि वेनेजुएला महत्वपूर्ण बाज़ार है।
- भारत को तेल की बिक्री से होने वाली आमदनी भी निकोलस मादुरो की सरकार के लयि वदिशी मुद्रा का बड़ा ज़रिया है। हालाँकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की गरिती कीमतों की वज़ह से यह कमाई अब गरिकर आधी रह गई है।

क्या है तात्कालिक संकट का कारण?

- मार्च 2013 में राष्ट्रपति हियूगो शावेज़ की मृत्यु के बाद निकोलस मादुरो ने सत्ता संभाली।
- अप्रैल 2013 में वेनेजुएला में हुए चुनाव में मादुरो ने वपिक्ष को हराकर राष्ट्रपति पद पर कब्ज़ा कयिा।
- दसिंबर 2015 में वपिक्षी लोकतांत्रिक एकता गठबंधन ने वेनेजुएला की नेशनल असेंबली का नियंत्रण अपने हाथ में लयिा।
- मार्च 2016 में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली का कार्यभार अपने हाथों में लयिा।

- जुलाई 2017 में राष्ट्रपति मादुरो पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया गया और वहाँ वधायी निकाय बनाने की मंजूरी देने के लिये जनमत संग्रह की बात कही गई।
- मई 2018 में मादुरो दोबारा राष्ट्रपति बने। उनका यह दूसरा कार्यकाल है, जो 6 साल तक चलेगा।
- वपिक्ष ने चुनाव में धाँधली का आरोप लगाया। 14 लैटिन अमेरिकी देशों सहित अमेरिका और कनाडा ने चुनावों को मान्यता देने से इनकार कर दिया।
- जनवरी 2019 में प्रमुख वपिक्षी नेता जुआन गाइदो ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ ने मान्यता दी।

शावेज़ ने कथि थे क्रांतिकारी बदलाव

दरअसल मादुरो के पूर्ववर्ती शावेज़ ने देश की बागडोर संभालने के बाद बहुसंख्यक जनता को मुख्यधारा में लाने के लिये सरकारी खज़ाने से गरीब वर्ग के स्वास्थ्य की सेहत, शिक्षा और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये तेल कंपनियों के राजस्व में से बड़ी हस्सेदारी मांगी और इन मदों पर खर्च किया। शावेज़ ने देश का राष्ट्रपति बनने के बाद कई कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, टैक्स बढ़ाए और गरीबों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास के लिये सरकारी पैसे से खूब काम किया। सामाजिक क्षेत्र में कथि गए उनके इन कामों ने शावेज़ को तेल के धनी देश का मसीहा जैसा बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें जब तक चढ़ती रहीं तब तक तो सब ठीक रहा, लेकिन आज तेल की गरिती कीमतों ने वेनेज़ुएला के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। वहाँ महँगाई आसमान पर है...रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों के लिये लोग परेशान हैं...और अर्थव्यवस्था की रीढ़ तेल का उत्पादन दिनों-दिन कम होता जा रहा है।

वेनेज़ुएला की आर्थिक बदहाली की कहानी

- अथाह तेल से भरे वेनेज़ुएला में आज लोग महँगाई और ज़रूरी चीज़ों की कमी से त्रस्त हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और बेरोज़गारी, अपराध तथा अराजकता का बोलबाला है।
- अगस्त 2018 में वेनेज़ुएला सरकार ने आर्थिक संकट से बाहर आने के लिये अपनी मुद्रा **बोलविर का 96** प्रतिशत तक अवमूल्यन किया था।
- तीन करोड़ की आबादी वाले वेनेज़ुएला का आर्थिक संकट 2014 में तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत दो तहियाँ से भी कम हो गई।
- इससे देश की आमदनी कम हो गई और बीते 3-4 साल से तेल बिक्री से होने वाली आमदनी में करीब 40 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है।
- इससे पहले 2016 के अंत में वेनेज़ुएला सरकार ने देश के सबसे अधिक मूल्य 100 बोलविर के बैंक नोट को सिकों से बदलने का नरिणय लिया था।
- वेनेज़ुएला सरकार ने यह फ़ैसला लंबे समय से चली आ रही खाद्य और दूसरी बुनियादी चीज़ों की कमी और तस्करी की समस्या से निपटने के लिये लिया था।
- इसका मकसद 'माफिया' पर रोक लगाना भी था ताक़ाँ काले धन को बाहर न भेज सकें।

वेनेज़ुएला के इस गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर में यहाँ महँगाई की दर दुनिया में सबसे अधिक है। आज हालत कुछ ऐसी है कि वेनेज़ुएला में लोग थैलों में नोट भरकर बाज़ार जाते हैं और उन पैसें से ज़रूरत का मामूली सामान खरीद पा रहे हैं।

वेनेज़ुएला की वरचुअल करेंसी 'पेट्रो'

फरवरी 2018 में वेनेज़ुएला को आर्थिक बदहाली से बचाने के लिये राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने नई वरचुअल करेंसी चलाई थी और वेनेज़ुएला के तेल, गैस, सोना तथा हीरा उद्योगों से इस नई मुद्रा का इस्तेमाल करने को कहा था। वेनेज़ुएला वरचुअल करेंसी 'पेट्रो' की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश है। वेनेज़ुएला सरकार ने शुरुआती बिक्री के लिये 'पेट्रो' की 3.84 करोड़ इकाइयों पेश की थीं। 'पेट्रो' दुनिया की पहली सरकारी मान्यता प्राप्त क्रिप्टोकॉइन है। तेल से होने वाली कमाई और मौजूदा मुद्रा बोलविर की गरिती कीमतों के मद्देनज़र तब यह कहा गया था नई वरचुअल करेंसी वेनेज़ुएला को पैसें के लेन-देन और रुकावटों से निपटने तथा आर्थिक तौर पर अपने पैसें पर खड़ा होने में मदद करेगी।

तेल पर आधारित है वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था

- लगभग दो दशक पहले ह्यूगो शावेज़ ने वेनेज़ुएला को तेल कंपनियों के फंदे से आज़ाद किया था, लेकिन अब वही वेनेज़ुएला बदहाली और मुश्किलों में घिरा है।
- शावेज़ के उत्तराधिकारी मादुरो की नीतियों से देश आर्थिक मुश्किलों के साथ राजनीतिक परेशानी का दौर भी देख रहा है।
- दरअसल, वेनेज़ुएला में तेल के अलावा और कोई घरेलू उद्योग नहीं है तथा सब चीज़ों के लिये आयात ही एकमात्र ज़रिया है।
- तेल की कीमतें गरिने के बाद लोगों के पास पैसा नहीं है और उन्हें दवा तथा रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिये भी कठिनाई हो रही है।

वेनेज़ुएला में सऊदी अरब से ज़्यादा बड़ा तेल का भंडार मौजूद है, लेकिन यहाँ का तेल कुछ अलग कसिम का है, जसिं **भारी पेट्रोलियम** कहा जाता है। भारी पेट्रोलियम का शोधन करना अपेक्षाकृत कठिन है और इस पर लागत भी अधिक आती है। यही वज़ह है कि दूसरे देशों की तुलना में वेनेज़ुएला के कच्चे तेल की कीमत कम है। फरि भी वेनेज़ुएला के कुल नरियात में 96 फीसदी हस्सेदारी केवल तेल की है।

अमेरिका ने लगाए प्रतर्बंध

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर वपिक्ष को सत्ता सौंपने का दबाव बनाने के लिये एक अहम आर्थिक कदम उठाते हुए अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA पर प्रतर्बंध लगा दिया है। इस प्रतर्बंध के तहत अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में कंपनी की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा और कोई भी अमेरिकी इस कंपनी के साथ किसी भी तरह का कारोबार नहीं कर पाएगा।

अमेरिकी राजनयिकों को पहले दिया देश निकाला, फरि वापस लया फ़ैसला

वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ संभावति टकराव को कम करने के लिये अमेरिकी राजनयिकों के देश छोड़ने के आदेश को फलिहाल स्थगति कर दिया है। दरअसल, अमेरिका ने वेनेजुएला में गहराते संकट में वरिधी नेता का पक्ष लेने का फ़ैसला कया था। इसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका के साथ संबंध तोड़ने का फ़ैसला कया था और ट्रंप प्रशासन के इस कदम को तख्तापलट की कोशिश करार दिया। बाद में उन्होंने राजनयिकों को 72 घंटे में देश छोड़कर जाने के अपने आदेश को वापस ले लया।

सुरक्षा परषिद में गरि अमेरिकी प्रस्ताव

वेनेजुएला के अंतरमि राष्ट्रपति के तौर पर जुआन गाइदो को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता दलाने का अमेरिकी प्रस्ताव सरि नहीं चढ़ सका। सुरक्षा परषिद में रूस और चीन के वीटो के चलते यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। रूस और चीन के अतरिकित सुरक्षा परषिद के अस्थायी सदस्य दक्षणि अफ्रीका और इक्वेटोरयिल गनिने ने भी अमेरिकी प्रस्ताव का वरिधि कया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परषिद की बैठक अमेरिकी वदिश मंत्री माइक पोंपयो के अनुरोध पर बुलाई गई थी। अमेरिका ने यह कदम वेनेजुएला के वपिक्ष के नेता को अंतरमि राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता देने के बाद उठाया था।

बातचीत के लिये तैयार हैं मादुरो

राजनीतिक संकट के दौर से गुज़र रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो संकट के समाधान के लिये वपिक्ष के साथ बातचीत के लिये तैयार हो गए हैं, परंतु आठ दनि के भीतर चुनाव चुनाव की घोषणा करने के अंतर्राष्ट्रीय अल्टीमेटम को उन्होंने खारजि कर दिया। मादुरो का कहना है कि वेनेजुएला की भलाई के लिये वह वपिक्ष के साथ बातचीत करने को तैयार हैं और जल्द ही संसदीय चुनाव कराने के पक्ष में भी हैं, क्योंकि समस्याओं के राजनीतिक समाधान का यह सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन उन्होंने समय से पहले राष्ट्रपति चुनाव कराने की संभावनाओं को खारजि करते हुए कहा कि इसके लिये तो 2025 तक इंतज़ार करना होगा। गौरतलब है कि मादुरो पछिले साल मई में राष्ट्रपति पद के लिये दोबारा चुने गए थे।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/venezuelan-crisis-going-towards-global-problem>

